IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ई -क्रांति की ओर बढ़ते कदम - डिजिटल इंडिया

Rajesh Kumar, Assistant Professor Govt. College Bhattu Kalan (Fatehabad)

Vikrant Mohan, Assistant Professor Govt. College Bhattu Kalan (Fatehabad)

परिचय-

भारत में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा "डिजिटल इंडिया" अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पूरे देश में अपने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना था। इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि के द्वारा देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया है । यह आम जनता तक पहुंचने का आसन तरीका है और उन्हें अपने दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई, 2015 को इस अभियान को शुरू किया गया । इस अभियान की सहायता से ग्रामीण भारत को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना है।

"डिजिटल इंडिया" अभियान के मुख्य घटक –

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

देश भर में विभिन्न डिजिटल सेवाओं को लागू करने में , विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना आवश्यक है। देश के आंतरिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या तो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश में डिजिटल नेटवर्क स्थापित करने के पीछे यही कारण है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, एक सरकारी निकाय जो राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना को लागु करने के लिए कार्य कर रही है , डिजिटल इंडिया परियोजना के लिए भी जिम्मेदार है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क का लक्ष्य देश भर में 2,50,500 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से एक हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पूरे देश में 4,00,000 इंटरनेट बिंदु स्थापित किए जाएंगे, जहां से हर कोई इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकेगा।

डिजिटल सेवा की डिलीवरी

डिजिटल इंडिया अभियान का एक प्रमुख घटक सरकारी सेवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना है।डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत सरकार की कई सेवाओं को डिजिटल किया गया।

इस योजना के तहत सभी मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा, और सभी विभाग मूलभूत सेवाओं जैसे स्वास्थ्य देखभाल, बैंकिंग, शिक्षा, छात्रवृत्ति, गैस सिलेंडर, पानी और बिजली के बिल और न्यायिक सेवाओं के साथ लोगों से जुड़ सकेंगे। लोगों के दैनिक वितीय लेन-देन को भी डिजिटल मोड में बदल दिया गया। लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सभी वितीय लेन-देन ऑनलाइन और वन टाइम पासवर्ड द्वारा सुरक्षित किए जा रहे हैं।

डिजिटल साक्षरता

डिजिटल इंडिया अभियान में भारत के सभी लोगों की पूर्ण भागीदारी के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, उसे डिजिटल साक्षरता कहते हैं। डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा , ज्ञान और कौशल अनिवार्य हैं। डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन डिजिटल उपकरण हैं जिनका उपयोग संचार, अभिव्यक्ति, मिल कर काम करने और नेटवर्किंग करने के उद्देश्य से किया जाता है। डिजिटल साक्षरता का मिशन छह करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को कवर करेगा।

डिजिटल इंडिया का लक्ष्य विकास क्षेत्रों के नौ स्तंभों पर अत्यधिक आवश्यक बल प्रदान करना है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में एक जटिल कार्यक्रम है और कई मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा हुआ है। डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभ नीचे दिए गए हैं:

- **ब्रॉडबैंड हाईवे** - इसमें तीन उप घटक शामिल हैं, अर्थात् सभी के लिए ब्रॉडबैंड –ग्रामीण , शहरी और राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना ।
- **मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस**- यह अभियान देश में नेटवर्क पहुंच और कनेक्टिविटी में अंतराल को कम करने पर पर केंद्रित है।
- **सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम**-सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के दो उप घटक-
  1- सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) 2 – डाकघर- बहु-सेवा केंद्रों के रूप में।
- **ई-गवर्नेंस:** प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार- सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए आईटी का उपयोग करके सरकारी प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग विभिन्न सरकारी डोमेन में सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इसे लागू करने की आवश्यकता है।
- **ई-क्रांति**- सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी- सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाना। इस संबंध में, विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ई-गवर्नेंस के युग में प्रवेश करने के लिए ई-गवर्नेंस से सम्बंधित कई कदम उठाये गये हैं। भारत में ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण से लेकर उन पहलों तक जो शासन के सूक्ष्म बिंदुओं को समाहित करती हैं, तेजी से विकसित हुआ है-जैसे कि नागरिक केंद्रितता, सेवा उन्मुखीकरण और पारदर्शिता।
- **सभी के लिए सूचना**- इस स्तंभ का उद्देश्य देश के लोगों के उपयोग, पुन: उपयोग और पुनर्वितरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उत्पन्न विश्वसनीय डेटा की पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण**- यह स्तंभ देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस करता है।
- **नौकरियों के लिए आई.टी**- यह स्तंभ आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशल हेतु युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **Early Harvest Programmes** - इस स्तंभ में विभिन्न अल्पकालिक परियोजनाओं का एक समूह जैसे कि बड़े पैमाने पर संदेश भेजने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म, ई-ग्रीटिंग्स की क्राउड सोर्सिंग, सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति, सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई आदि शामिल है, जो भारतीय डिजिटल सिस्टम पर तत्काल प्रभाव डालते हैं ।

डिजिटल इंडिया पहल

डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार ने कई कदम उठाये हैं।ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण स्कीम निम्नलिखित हैं -

- **सुलभ भारत अभियान और मोबाइल ऐप**- इसे सुगम्य भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य सभी प्रकार की सेवाओं को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करवाना है।
- **Mygov.in**- यह मंच उपयोगकर्ताओं को सरकार की प्रशासन रणनीति पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है। इसे इसलिए लागू किया गया है ताकि स्थानीय लोग सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

- **नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (UMANG)**- इस मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी भी डिवाइस पर किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह सॉफ़्टवेयर उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाओं तक पहुँचने की अनुमति देता है। उमंग एप्प पर उपलब्ध सेवाओं में शिक्षा पोर्टल, डिजिटल लॉकर,पासपोर्ट सेवा,भारत बिल भुगतान सेवा, गैस सेवा,फसल बीमा, आधार, टैक्स और ट्रेन टिकट खरीदारी शामिल हैं।

- **कृषि बाजार ऐप**- इसे किसानों को कृषि कीमतों से अवगत कराने और उन्हें फसल बेचते समाय जल्दबाजी न करने के उद्देश्य के लिए बनाया गया था।

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**- एक बालिका के कल्याण और पोषण को सुनिश्चित करना और यह भी सुनिश्चित करना कि हर लड़की स्कूल जाती है ।

- **भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम)**- यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जल्दी, आसानी से और सरलता से भुगतान करता है। यह बैंक को मोबाइल फोन नंबरों का उपयोग करके तत्काल भुगतान और धन संग्रह स्वीकार करने की भी अनुमति देता है

- **फसल बीमा मोबाइल ऐप**- यदि कोई ऋण लिया जाता है, तो क्षेत्र या ऋण राशि जैसी कई विशेषताओं के आधार पर फसल बीमा प्रीमियम की गणना करने के लिए **ऐप** उपयोग किया जाता है।

- **ई-अस्पताल**- यह अस्पतालों के आंतरिक कार्यप्रणाली और संचालन के लिए एक HMIS (अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली) है।

- **E-Pathshala**- नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने विद्यार्थिओं से सम्बंधित सभी प्रकार की पुस्तकों , टेक्स्ट बुक्स,ऑडियो **,** विडियो के अतिरिक्त अन्य डिजिटल संसाधनों को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने के लिए बनाया है।

- **ईपीएफओ वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप**- यह ऐप कर्मचारियों को ई-पासबुक का उपयोग करके अपने भविष्य निधि की राशि की जांच करने की अनुमति प्रदान करती है , जो वास्तविक पासबुक के जैसी होती है।

- **स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल और मोबाइल ऐप**- यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो उद्यमियों को देश में नये व्यवसायों (स्टार्ट-अप) को विकसित करने और स्थायी रूप से विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

डिजिटल इंडिया के उद्देश्य

- यह अभियान स्वास्थ्य देखभाल और साक्षरता को और अधिक सुलभ बनाता है। परम्परागत तरीके की अपेक्षा डॉक्टर की नियुक्ति, शुल्क का भुगतान, डायग्नोस्टिक परीक्षण और रक्त परीक्षण हेतु ऑनलाइन पंजीकरण आसानी से और घर बैठे ही किया जा सकता है है।

- यह उपभोक्ताओं को परम्परागत थकान भरे भौतिक कार्य को कम करते हुए कहीं से भी अपने कागजी कार्रवाई और प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देता है।

- नागरिक डिजिटल रूप से अपने रिकॉर्ड पर ऑनलाइन हस्ताक्षर कर सकते हैं।

- यह राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के लाभार्थियों को आवेदन ऑनलाइन जमा करने, उन्हें सत्यापित करने और भुगतान करने की अनुमति देकर लाभान्वित करता है।

- बीएसएनएल मोबाइल उपकरणों पर वॉयस, डेटा, मल्टीमीडिया आदि जैसे ऑनलाइन सेवाओं के बेहतर प्रशासन के लिए 30 साल पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की जगह लेगा।

- सभी प्रकार के वितीय लेन-देन डिजिटल तरीके से पूरे किए जाते हैं, इस प्रकार यह कालाबाजारी को कम करने में भी सहायक होता है।

डिजिटल इंडिया मिशन के लाभ

डिजिटल इंडिया मिशन एक ऐसा कदम है जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभों में से एक है। डिजिटल सिस्टम अपनाने के मंच पर, भारत विश्व में शीर्ष 2 देशों में शामिल है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 तक $1 ट्रिलियन को पार करने की संभावना है।

डिजिटल इंडिया के कुछ लाभ हैं:

- ई-गवर्नेंस से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक फाइंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में वित्तीय समावेशन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही और खाताधारकों की संख्या जो 2011 में 35 फीसदी थी और 2014 में 53 फीसदी थी। वह 2017 में बढ़कर 80 फीसदी हो गई है।
- भारत नेट कार्यक्रम के तहत 2,74,246 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ने 1.15 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा है।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत एक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) बनाया गया है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तक पहुंच प्रदान करता है। कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से, सीएससी ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन और अन्य सरकारी और निजी सेवाओं से संबंधित मल्टीमीडिया सामग्री प्रदान करते हैं।
- सोलर लाइटिंग, एलईडी असेंबली यूनिट, सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन यूनिट और वाई-फाई चौपाल जैसी सर्वसुविधायुक्त सुविधाओं के साथ डिजिटल गांवों की स्थापना।
- इंटरनेट डेटा का उपयोग सेवाओं के वितरण के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में किया जाता है और शहरी इंटरनेट की पहुंच 64% तक पहुंच गई है।
- देश के लगभग 80 प्रतिशत लोग बैंक में अपना खता खुलवा चुके है । ग्रामीण स्तर पर भी लोगो द्वारा बैंकिग माध्यम से वितीय लेनदेन किये जाने लगे हैं ।

डिजिटल इंडिया की चुनौतियाँ

भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहल की है। डिजिटल इंडिया अभियान में सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के अतिरिक्त इसमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है।

डिजिटल मिशन की कुछ चुनौतियाँ और कमियाँ नीचे दी गई हैं:

- भारत में अन्य विकसित देशों की तुलना में दैनिक इंटरनेट गति और वाई-फाई हॉटस्पॉट की गति धीमी हैं।
- अधिकांश छोटे और मध्यम उद्योग को नई आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
- सुगम इंटरनेट एक्सेस के लिए शुरुआती स्तर के स्मार्टफोन की सीमित क्षमता।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल मानवीय संशाधन की कमी।
- डिजिटल अपराध के बढ़ते खतरे की जांच और निगरानी के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की नियुक्ति भी एक चुनौती है ।
- डिजिटल शिक्षा का अभाव।
- संस्कृति की दृष्टि से भारत एक विविधतापूर्ण देश है। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट भाषा, रीति-रिवाज, खान-पान, कानून और परंपराएँ होती हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य पूरे देश को डिजिटल रूप से एकीकृत करना है। पूर्ण एकीकरण जो प्रौद्योगिकी और भाषा का एकीकरण है, मिशन को इसके कार्यान्वयन में सामना करने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक है।

निष्कर्ष

डिजिटल रूप से जुड़े भारत का उद्देश्य देश में जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विकास करना है। गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों का विकास वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए ऐसी उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अकेले किसी देश के समग्र विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकती है। बुनियादी डिजिटल ढांचा समग्र विकास हासिल करने में मदद कर सकता है।

साक्षरता और विनियामक व्यावसायिक वातावरण भी इसे प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यह एक बहुत ही लाभदायक दृष्टिकोण होगा क्योंकि यह कागजी कार्रवाई पर समय खर्च करने के बोझ से राहत देता है और लोगों को अपना समय सरकार के अन्य पहलुओं को समर्पित करने की अनुमति देता है। यह बड़े पैमाने पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद कुशल और फायदेमंद है।

REFERENCES:

https://yojana.divyabihar.com/umang-app/

https://knowledgemaps.org/e-pathshala-app-in-hindi/

Himakshi Goswami (2016)“OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF DIGITAL INDIA PROGRAMME E” ISSN No : 2454-9916 | Volume - 2 |

ErHarjotKaur and MrsDaljitKaur (2015),” E-commerce in India – challenges and prospects” International Journal of Engineering and Techniques, Vol-1, issue 2, pg No- 36- 40.

Digital India, a programme to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy, Department of Electronics and Information Technology, Government of India, available at www.slideshare.net.

3. Recommendation of the council on digital Government strategies, adopted by the th OECD council on 15 July 2014, OECD.

4. M.M.K Sardana(2012),” Vision of Digital india challenges ahead for political establishment DN2012/09,ISID.

5. Usha Rani Das, challenges of Digital India some heads –up of NarendraModi, Business insider India.

6. Digital India power to empower, available at www.nextgenias.com/2015/09/eassydigital-india-programme-upsc-ias

7. Kaur,P.and Joshi, M.M., “E-Commerce in India: A Review”, IJCST,Vol.3, Issue 1,JanMarch 2012,pp-802-804

8. Kaur,Ranmeet, E-Commerce in India, Asian journal of research in business economics and management, vol.2, issue 6,2012

9. ERNET: Education and Research Network, an autonomous scientific society of Ministry of Communications and Information Technology (Govt. of India).

10. Balasubramanian, D. (2013), 'Sixty years of IT in India,' The Hindu, February 20.

11. e-governance: Reforming government through technology.

12. e-kranti: Electronic delivery of services.

https://www.vedantu.com/english/digital-india

https://www.livehindustan.com/national/story-as-per-world-bank-report-number-of-bank-accounts-in-india-increased-27-percent-in-last-four-year-tenure-of-narendra-modi-government-1914063.html